पृथ्वी पर हम सब समय माया के यात्री हैं

साप्ताहिक

समय माया

R.N.I. No.: MP/HIN/2006/20685
www.samaymaya.com

प्रधान संपादक- अजमेरा एस.पी. कुमार
B.COM., M.A., LLB, CAIIB, DLLLW&PM

Webite: www.samaymaya.com
Email: samaymaya@gmail.com
samaymaya@rediff.com

Cell: +91 9425125569
+91 9479535569

(C) All Copyrights reserved with chief editor, do not publish any matter without prior written permission

In case of any dispute, may be solved only in Indore Court Jurisdiction

वर्ष 17 | अंक 19 | प्रति सोमवार इंदौर, 11 दिसंबर से 17 दिसंबर 2023 | पृष्ठ 8 | मूल्य 5/- रुपए

जनता सड़कों पर आओ ईवीएम के विरुद्ध आवाज उठाओ लोकतंत्र बचाओ

ईवीएम हटाओ लोकतंत्र व देश बचाओ

सारा विपक्ष एक हो जनता को सड़कों पर निकाल ईवीएम के विरुद्ध आंदोलन करो या गुलाम हो जाओ

ईवीएम मशीनों की हैकिंग के बारे में तो आप बहुत कुछ देख सुन रहे हैं। परंतु मेरे लगातार सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों के संपर्क में आने के बाद कई ऐसे तथ्य बातचीत में हाथ लगे जो बहुत छोटी सी बात को समझने में बहुत आसानी होगी।

अधिकांश कर्मचारी अधिकारी जो चुनाव की गिनती में बैठे हुए थे. सब ने बताया जो मशीन मतदान से पहले दिन चार्ज की गई थी उसके बाद चुनाव करवाया गया और बाद में 15 दिन स्ट्रांग रूम के ताले में बंद कर दिया गया. तो मशीन बंद कर देने के बाद में भी ज्यादा से ज्यादा उसमें 25- 30% ही चार्जिंग रहनी चाहिए थी। जो की गिनती के समय 95 से 98% तक थी अर्थात स्ट्रांग में ताला बाहर से लगा हुआ था और मशीन अंदर से खोलकर मोबाइल लिया कंप्यूटर से सेल लगे होने के बाद में भी पोर्ट से जो खुले हुए थे आसानी से सब बदल दी गई और यही कारण था की 26 नवंबर के बाद सारी मशीन पूरे प्रदेश की बदल दी गई तो शिवराज को और सत्ता को ज्यादा तकलीफ देने लगे थे मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देखने लगे थे जिनको हराना था। उनके अतिरिक्त 63 सीट देकर बाकी सारी सीटों पर फेर बदल करने के बाद में सारे मीडिया को खबर पहुंचाई गई और जहां भाजपा को 60 सीट मिल रही थी वहां 160 हो जाने के बाद जनता को मीडिया के माध्यम से उसके दिमाग को परिवर्तित करने के लिए जालसाजी के बाद भाजपा के जीतने की धुन सुनाई जाने लगी। ताकि जनता एकदम भड़क न जाए और सारे के सारे लोगों के मानसून को पानी फेरने उनका मानसिक रूप से तैयार करने के लिए सारी कहानी बदलकर सुनाई जाने लगी। जो फर्जीवाड़े का उत्कृष्ट उदाहरण था।

ईवीएम मशीन यथार्थ में उसको हैकिंग बैंकिंग की जरूरत ही नहीं है। मशीन में आसानी से सॉफ्टवेयर डालकर उससे आप उसकी संरचना के अनुसार अपनी इच्छा अनुसार परिणाम ले सकने के लिए स्वतंत्र है। मशीन को ऊपर से लॉक किया जाता है जबकि उसके सारे यूएसबी पोर्ट खुले रहते हैं। जिससे कंप्यूटर से उसमें उम्मीदवारों के नाम भरे जाते हैं।

सॉफ्टवेयर डालकर कमांड दी जाती है। जिसे आसानी से आप मशीन में मतदान होने के बाद केंद्र पर लाने के बाद मशीन की सील वही लगी रहेगी। आप कुछ नहीं यूएसबी पोर्ट से कंप्यूटर से कनेक्ट कर मन चाहे परिणाम डाल अपना इच्छित कार्य पूरा कर सकते हैं।

क्योंकि सील ऊपर लगाई जाती है पोर्ट से चार्जिंग के साथ जो चाहे जैसा चाहो कर लो अगर मशीन नहीं भी बदलते हो तो इस मशीन में आसानी से कंप्यूटर से या मोबाइल से कनेक्ट कर जो तत्काल आपको उस मशीन के मेमोरी कार्ड में क्या है वह बताती है कि उसे आप अपने आसानी से बदलकर जिसे चाहे ज़िताओ और हराओ।

इसलिए आवश्यक है सबसे पहले ईवीएम मशीन हटाओ।

आज का गाना

फ़िल्म- प्यासा सावन

इसलिए सभी विपक्षी दल और जनता सड़कों पर आओ। जोर से आवाज लगाओताकि सर्वोच्च न्यायालय के अंधे बहरे कानून और उसका पालन करवाने वाले बिके हुए या सत्ताधीशों के पाले बैठाये हुए अंकल जजों को सुनाई पड़ जाए। ईवीएम हटाओ देश बचाओ वरना सब भिखारी बन रु. 1 किलो के गेहूं और रु.2 किलो के चावल की लाइन में लग गुलामी की तरह जीवन जीने में लग जाओ।

वर्षों से बोल रहे हैं, की सबसे पहले इवीएम हटवाओ। देश बचाओ।

आखिर 15 दिन में पूरी इवीएम बदल दी गईं। और यही कारण था कि पूरा का पूरा चुनाव के मतदान के बाद बड़ी शान से भेड़िया झुंड पार्टी इसी ईवीएम बदले जाने के दम पर जीत का दावा कर रही थी।

परिणाम सामने है अब कोई भी चुनाव इवीएम से ना हो। इसके लिए सारी पार्टीयां सड़कों पर निकल आए और इवीएम के खिलाफ पूरे देश में युद्ध छोड़ दें।

वरना पूरे छत्तीसगढ़ की पूरी खदानें अदानी को सौंप दी जाएंगी अब।

अंध भक्तों के साथ पूरी जनता को लूटने गुलाम बनाने जनता की मूलभूत आवश्यकताओं को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के इशारे पर नाच कर शिक्षा स्वास्थ्य बिजली पानी सड़कें सब बेचने गिरवी करने पेड पर देने का षड्यंत्र कर नोचने के लिए खुला छोड़ दिया जाएगा।

(शेष पेज 6 पर)

चीन ने सैन्य रसद समर्थन के लिए बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, म्यांमार पर विचार : पेंटागन रिपोर्ट

पेंटागन के निष्कर्षों में यह भी बताया गया है कि चीन ने पूर्वी लद्दाख में भारत के साथ 2020 के गलवान गतिरोध के बाद से वास्तविक नियंत्रण रेखा पर बलों की तैनाती और बुनियादी ढांचे का निर्माण बढ़ा दिया है।

चीन वैश्विक सैन्य पदचिह्नों का विस्तार करने की कोशिश कर रहा है, पेंटागन की नवीनतम रिपोर्ट में जिबूती और कंबोडिया के रीम नेवल बेस के अलावा 18 देशों का नाम लिया गया है, जिसमें जोर देकर कहा गया है कि बीजिंग ने उन्हें 'शायद' 'पीएलए (पीपुल्स लिबरेशन आर्मी) सैन्य रसद के लिए स्थान' के रूप में 'विचार' किया है।

चीन के बाहर मानी जाने वाली इन रक्षा सुविधाओं में से चार भारत के तत्काल पड़ोसी हैं - बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान और बर्मा (म्यांमार) और उनमें से अन्य तीन - थाईलैंड, सिंगापुर, और इंडोनेशिया - अमेरिकी रक्षा विभाग की कांग्रेस की वार्षिक रिपोर्ट 'चीन के जनवादी गणराज्य से जुड़े सैन्य और सुरक्षा विकास 2023' के अनुसार, दक्षिण पूर्व एशिया में हैं।

'पीआरसी (पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना) ने शायद अन्य देशों को भी पीएलए सैन्य रसद सुविधाओं के लिए स्थानों के रूप में माना है, जिनमें बर्मा, थाईलैंड, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, संयुक्त अरब अमीरात, केन्या, इक्वेटोरियल गिनी, सेशेल्स, तंजानिया, अंगोला शामिल हैं। नाइजीरिया, नामीबिया, मोज़ाम्बिक, बांग्लादेश, पापुआ न्यू गिनी, सोलोमन द्वीप और ताजिकिस्तान, 'इस महीने अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा जारी वार्षिक रिपोर्ट में कहा गया है।

भारत की सीमाएँ: भारत के पड़ोसी देश अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चीन, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका हैं। भारत उत्तरी गोलार्ध में अक्षांशीय रूप से और पूर्वी गोलार्ध में अनुदैर्ध्य रूप से स्थित है।

भारत के पड़ोसी देशों के नाम बताएं: भारत 9 देशों के साथ सीमा साझा करता है और उत्तरी गोलार्ध में अक्षांशीय और पूर्वी गोलार्ध में अनुदैर्ध्य रूप से स्थित है। इस लेख में, हमने भारत के पड़ोसी देशों और उनकी सीमा से लगे भारतीय राज्यों की एक सूची तैयार की है। यह सूची छात्रों के सामान्य ज्ञान को बढ़ाएगी और उन्हें विभिन्न शैक्षणिक और प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में भारत के भूगोल से संबंधित प्रश्नों से निपटने में मदद करेगी।

भारत की स्थलीय सीमा 15,200 कि.मी. है। मुख्य भूमि, लक्षद्वीप द्वीप समूह और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की समुद्र तट की कुल लंबाई 7,516.6 किमी है। **(शेष पेज 7 पर)**

संपादकीय

अपराधियों, जालसाजों के देश में कैसा लोकतंत्र

पिछली 20 व 21वीं शताब्दी में विश्व में विद्युत के जन्म के बाद इलेक्ट्रॉनिक्स के विकास के साथ, सभी प्रकार के सामाजिक, आर्थिक व नैतिक मूल्यों का पतन हुआ, हो रहा और होता रहेगा। तत्काल में देश में हुए चुनावों मैं जिस प्रकार सत्ता में बैठे अपराधियों ने जनता की आवाज को कुचल सत्ता हथियाई है उससे न केवल राजनैतिक दलों के साथ जनता में घोर निराशा छाई हुई है। विद्युत की जन्म के बाद विद्युतीय उपकरणों ने जीवन को सरल अवश्य बनाया था। परंतु वैद्युतकीय विकास के साथ मेरे जीवन सरल और सुलभ हुआ परंतु मानव के लालच ने हीं जैसे ही दूरसंचार की क्रांति को जन्म दिया। उसके उपयोग व सदुपयोग बढ़ने के साथ-साथ घातक दुरुपयोग बढ़ने लगे और वे इस तेजी से बढ़े। कि मनुष्य का जीवन का अधिकांश समय राक्षसों की भांति मानसिक व शारीरिक रूप से कमजोर करते हुए हजम करने लगे। संगणकों के जन्म उत्पादन और बढ़ते प्रयोग के बादजो अगली सबसे खतरनाक क्रांति हुई वह थी सन्गणकों को पूरे विश्व में जोड़कर सबकी जीवन में रखें चलित दुर्भाषों के माध्यम से न केवल गोपनीयता भंग करना उनके सारे राज इकट्ठे करना उसके आधार पर उसमें से न केवल बैंक खातों में डकैती डालना, लूटना, चित्रों चलित चल चित्रों को, आवाज को बदलना अश्लील बनाना ब्लैकमेल करना जो कि व्यक्तिगत स्तर से लेकर राष्ट्र के शासकीय तंत्र और राजनीतिक दलों में भी छाया हुआ है। इन सबके दुरुपयोगों ने हर स्तर पर अपराधियों को मजबूत करने बुलंद बनाने छल कपट करके हर तरह से सामाजिक आर्थिक नैतिक सुरक्षा को समाप्त कर आम जनता की जिंदगी को शारीरिक मानसिक रूप से परेशान किया है। तत्काल में हुए चुनाव में उस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की जालसाजी से सत्ता में बैठे अपराधियों जो प्रशासनिक अधिकारियों व नेताओं ने पूरे तीन प्रदेशों के परिणामों को बदलकर जनता की आत्मा की आवाज को कुचल कर कोई बहुत महान काम नहीं किया। क्योंकि छल, कपट, जालसाजी कर कब तक सत्ता हथिया के सुख भोग लोगे, इसके विपरीत महंगाई बेरोजगारी भूख से पीड़ित त्रस्त पूरी जनता के मस्तिष्क से निकलने वाली आह वह पीड़ा की तरंगें वैद्युतकीय उपकरणों को पीछे छोड़ प्राकृतिक स्तर परअपना खेल-खेलकर संगीत होसत्ता तंत्र को नष्ट करने के साथ खंड-खंड बिखेरने में भी सक्षम है। क्योंकि संगणकों और सूचना तंत्र के मकड़जाल की चलित दुर्भाषों जो विश्व में लगभग 4 सौ करोड़ से ज्यादा हैं मस्तिष्क की तरंगों को पकड़ने में सक्षम बनाया जा रहा है? व उससे विकसित कृत्रिम बुद्धिमता को स्वच्छ बनाने की कोशिश की जा रही है। परंतु प्रकृति प्रदत्त मानव मस्तिष्क को पढ़ने की योग्यता में अभी इतना योग्य व सक्षम नहीं हुआ। जो इन अपराधियों को प्रकृति के कर और भर के दंड देने से सुरक्षा प्रदान कर सके जो प्रकृति का अटल सत्य है। जिस पर मानव निर्मित यह बात की उपकरण नियंत्रण कर सकें ठीक है। इस समय के साथ अपराधी उसका दुरुपयोग कर अपने आप को सक्षम मान जनता को पीड़ित करते रह सकें। बेशक कुछ समय के लिए जनता की आवाज को घोंटकर लोकतंत्र की हत्या कर साधनों के दुरुपयोग से अपराधी लूट तंत्र बना बर्बाद कर सकते हैं।

प्रदेश की सभी सरकारी सेवाओं में अनावश्यक अत्यधिक 10 गुना तक लूट

शासकीय निविदा भरने, कार्यों में ठेकेदारों से दलाली के साथ भी लूट

50 से 70% तक कमीशन खाने के बाद में भी अधिकारी ठेकेदारों को उलझाने के बाद भी मुश्किल से भुगतान आत्महत्या तक को मजबूर

पूरे प्रदेश में 20 साल से शासन कर रही भाजपा ने अपनी मोटी कमाई, लूटने भ्रष्टाचार के लिए पूरे प्रदेश को प्रदेश के सभी शासकीय विभागों में आपूर्ति, निर्माण, मरम्मत, सुधार, क्रय, विक्रय, सेवायें आदि के कार्य करने वालों ठेकेदारों को हर तरीके से परेशान करने के बाद में भी महीनों से वर्षों तक भुगतान नहीं किया जाता है। जिस ठेकेदार मजदूरों के साथ सामग्री आपूर्ति कर्ताओं को ब्याज पर उठाकर पैसा भुगतान करने के लिए बाध्य हो जाते हैं।

इन सब के पीछे नगर निगमों, पालिकाओं, परिषदों पंचायतों से लेकर लोक निर्माण विभाग, के अलग-अलग भवन एवं पथ, सेतु, भवन, सड़क डकैती विकास निगम, विद्युत एवं यांत्रिकीय, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय, के भी नलकूप खनन,जलापूर्ति निर्माण,रखरखाव के साथ जल निगम, विद्युत एवं यांत्रिकीय, जल संसाधन, नर्मदा घाटी, पुलिस हाउसिंग, गृह निर्माण मंडल, विकास प्राधिकरणों, शिक्षा, कृषि, उद्यानिकी, गृह एवं जेल विभाग, विद्युत कंपनियां, वाणिज्य कर, मत्स्य आदिम जाति कल्याण, जनजाति, अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं विकास, परिवहन, उद्योग एवं व्यापार, औद्योगिक केंद्रीय विकास निगम, मंडी, स्वास्थ्य, वन, महिला बाल विकास, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, खाद्य एवं औषधि विभाग, आबकारी, प्रदूषण मंडल आदि आदि के सभी विभागों में ठेकेदारों से 10 से 50 से 90% कमीशन खाने के, भारतीय प्रताड़ना सेवा के अधिकारियों एडीएम एसडीएम डीएम से लेकर आयुक्त सचिव प्रधान सचिव बाद में भी नीचे उपयंत्रियों बिल बनाने पास करने वाले बाबूओं से लेखा अधिकारियों तक सबका अपना कमीशन होने के साथ ठेकेदारों से प्रारंभ से ही निविदा देखने, प्रपत्र खरीदने भरने में भी निरर्थक भारी लूट व जाल साजियां की जाती हैं। जिसमें पूर्व में टीसीएस में हजारों करोड़ का घोटाला कर पैसे हजम करके निकल गई दूसरी तरफ जब साइट केंद्र सरकार के नेशनल इनफॉर्मेटिक्स सेंटर की है, तो निविदा प्रपत्र का प्रोसेसिंग का भारी भरकम शुल्क क्यों आखिर ठेकेदार सरकार के जनता से जुड़े हुए विभागों के लिए आपूर्ति व सेवाएं देने का काम करता है। तो वह शत्रु तो नहीं, जिससे मनचाही लूट करो भुगतान के नाम पर हर कदम पर उसको नोचों, यदि कर्मचारियों से लेकर मंत्रियों अधिकारियों की लूट और मनचाही वसूली देने के बाद में भी समय पर भुगतान न दो। तो आखिर वह सम्मान के साथ जीवन यापन करने के लिए धन अर्जन करने आया था। या सारी परेशानियों को जेल कर भुगतान के नाम पर परेशान होकर आत्महत्या करने के लिए।

जैसा कि अभी आपने देखा की नगर निगम में पप्पू भाटिया नाम के अच्छे ठेकेदार नहीं अधिकारियों की लूट वसूली के बाद में भी भुगतान न देने के कारण आत्महत्या कर ली इसके बाद में भी उन जालसाज डकैत भ्रष्ट निकम्में लुटेरे अधिकारियों को बचाने के प्रयास में पुलिस से लेकर भोपाल स्तर तक के सभी अधिकारी जुटे हुए हैं और जिसका इस प्रकरण में घिर जाना तय है।

सीटी इंजीनियर राठौर को ऐच्छिक सेवानिवृत्ति देकर भगाने का षड्यंत्र किया जा रहा है। आखिर स्वर्गीय पप्पू भाटिया के मोबाइल नंबर से जुड़े हुए सारे निगम के अधिकारियों कर्मचारियों के पिछले साल भर के मोबाइल के बातचीत के टेप क्यों नहीं निकल जा रहे ताकि सच्चाई का पता लगाया जाकर दोषी कर्मचारियों अधिकारियों को दंडित किया जा सके परंतु ऐसा कभी नहीं होगा क्योंकि भ्रष्टाचार के मामले में इंदौर नगर निगम के 7 बार के फर्जी स्वच्छता के प्रमाण पत्र की तरह भ्रष्टाचार के भी अपनी श्रेष्ठ के प्रमाण पत्र हैं। फिर निगमायुक्त से लेकर अधिकांश इंजीनियर डॉक्टर और राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी आखिर क्यों लाखों रुपए देकर पद हत्याथे हैं और फिर मासिक भेड़िया निधि चुका अधिकतम 3 वर्ष की प्रति नियुक्ति की अपेक्षा वर्षों तक मोटा धन अर्जित करते हुए कुर्सियों से चिपके व चिपकाए रहते हैं। उसके पीछे एकमात्र कारण व शब्द होता है भ्रष्टाचार से लूटो और लुटाओ।

तू आखिर कब तक प्रदेश के सभी विभागों के ठेकेदार इन आर्थिक व नैतिक परेशानियों से उलझकर कर्ज में डूबे रह जीवन यापन कर सकेंगे। आखिर में भी सरकार का हिस्सा है और यह लजो नीचे प्रस्तुत की जा रही है सरकार न केवल उनका निराकरण करें वरन हर कार्य की भुगतान की समय सीमा निश्चित करें अन्यथा 18% की दर से ब्याज देने की अन्य कार्यों की गारंटीयों की तरह गारंटी दे।

म.प्र. में निविदा प्रपत्र की जो कीमत रखी गई हे जो की 1000 रु से ले कर 50000 तक रखी गई है उसका क्या उपयोग होता है जबकि सारी निविदाएं ऑनलाइन लगाई जाती है और जो की कुल 100 पन्नो की होती है, जबकि केंद्र सरकार के इस से बड़े निविदा प्रपत्र की कीमत भी 1000 से अधिक नहीं होती है। एक तरह से ठेकेदारों के साथ लूट मचा राखी है और तो और अगर निविदा एक बार खोल दी जाती है उसके बाद निरस्त कर के फिर से लगाई जाती है तो पूर्व में दी गई राशि भी वापसी नहीं की जाती है जबकि केंद्र सरकार द्वारा उक्त राशि का DD बनवाया जाता है एवं L1 ठेकेदार से ही निविदा प्रपत्र की राशि जमा करवाई जाती है यही प्रक्रिया बेंको द्वारा भी की जाती है किन्तु म.प्र. शासन में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है लूट की दुकान लगा रखी है और तो और म.प्र. शासन के निविदा प्रपत्र में ठेकेदारों के हित की एक भी शर्त नहीं रखी गई है एवं अनुबंध के समय ली जाने वाली राशि 5% रखी गई है एवं भुगतान के वक्त 5% और काट ली जाती है जो की कुल 10% होती है जबकि केंद्र सरकार मात्र 2.5% ही लेती है और ना ही अनबेरेक्बल दर के नाम पर और अतिरिक्त राशि जमा करवाई जाती है किन्तु म.प्र शासन द्वारा ऐसी व्यवस्था कर दी गई है की छोटी पूंजी वाले ठेकेदार इनके विभागों में काम ही नहीं ले पाए और ऑनलाइन पोर्टल पर प्रोसेसिंग फीस के नाम पर 250 रु से ले कर 1500 रु लिए जा रहे है जो की अरबों रु की राशि होती है वह किसके पास जा रही है उसका भी कुछ पता नहीं है जबकि उक्त पोर्टल केंद्र साशन के NIC के स्वमित्व का है अतः उक्त राशि किसके पास जा रही है और यह राशि ठेकेदारों से अलग से क्यों ली जा रही है जबकि निविदा बुलाने और खोलने का काम म.प्र शासन का है तो उसका भार भी म.प्र. शासन को उठाना चाहिए।

सावधान संपत्ति खरीदने वालों

इन्दौर। भूसंपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) ने इन्दौर जिले में 32 रहवासी परियोजनाओं के रजिस्ट्रेशन आवेदनों को निरस्त कर दिया है। कालोनाइजर/बिल्डर अब इन परियोजनाओं के तहत व्यवसाय नहीं कर सकेंगे। वहीं रेरा ने आम जनता को सलाह दी है कि वे इन 32 परियोजनाओं में किसी तरह की खरीदी या बुकिंग न करें। इन परियोजनाओं में शहर के साथ ग्रामीण क्षेत्र की परियोजनाएं भी शामिल हैं। रेरा ने जिन कालोनियों के आवेदन निरस्त किए हैं उनमें श्रीनाथ हिल्स, महू वायब्रेट विनी कमर्शियल, बिचौली हप्सी, द लैंड मार्क स्कीम नं. 94 खजराना, श्री विहार सांवेर, स्काय फ्लोरेस निपानिया, बृजविहार ग्राम पंजडोरिया, सनफ्लावर वेली उमरिया, कॉरडोर इंडस्ट्रीयल पार्क टिगरिया बादशाह, तुलसी एनक्लेव किशनगंज, भूमि सोलिटायर पिपल्याहाना, रुचि एनक्लेव निपानिया, ड्रीम विक्टोरिया पालाखेड़ी, शांती मार मेला महू, टोरियां पार्क सांवेर, मिलन ग्रांड बिचौली हप्सी, श्रीकृष्णा शंखेश्वर सिटी,जाखिया, साहिल सत्यराज, बसंत बिहार कालोनी, होम साल्यूशन खजराना आदि कालोनियां तथा टाउनशिप शामिल है।

स्वास्थ्य विभाग जालसाज डाक्टरों व लुटेरों का अड्डा

नियम कानून को ताक रख मनमर्जी से खरीदी व जनधन का दुरूपयोग

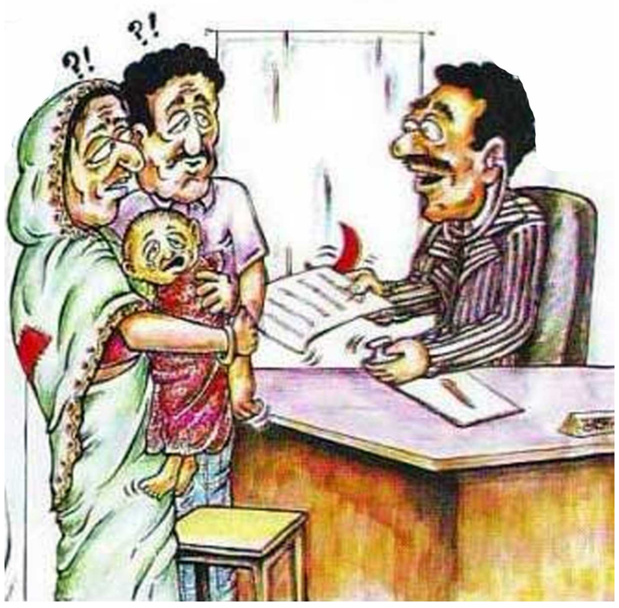

सूचना के अधिकार में जानकारी मांगने पर हजारों के बिल, धारा 4 का पालन नहीं

मध्य प्रदेश शासन के स्वास्थ्य विभाग में बैठाये गए अतिरिक्त मुख्य सचिव इंजीनियर मो. सुलेमान सचिन के रूप में डॉक्टर सुदाम खाड़े, अतिरिक्त सचिव के रूप में राकेश श्रीवास्तव तीनों ही भारतीय प्रताड़ना सेवा के अधिकारी हैं जो घोर जालसाज डकैत और लुटेरे होते हैं। और पिछले कई वर्षों से एक ही स्थान पर बैठकर स्वास्थ्य विभाग की विभिन्न विभागों चिकित्सा महाविद्यालयों की औषधीयों उपकरणों, सामग्री की खरीदी में 70% कमीशन पर स्तरहीन लाखों प्रकार की औषधियों, सामानों के साथ, डॉक्टरों कर्मचारियों की राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन व अन्य विभागों में ठेके पर संविदा कर्मियों की नियुक्तियों, स्थानांतरण में नियमों कानूनों कि धज्जियां बिखेर अपनी मोटी कमाई करने में लगे हुए हैं। बेशक उसे मोटी कमाई में से मुख्यमंत्री स्वास्थ्य मंत्री के साथ में केंद्रीय मंत्रियों को भी विभिन्न प्रकार की चिकित्सा योजनाओं में आवंटन के विरुद्ध एक निश्चित कमिशन दिल्ली तक पहुंचाना पड़ता है।

बेशक इस काम में जिलों के मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारियों से लेकर नीचे ग्रामीण स्तर पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तक बैठे कर्मचारियों डॉक्टरों तक भ्रष्टाचार बॉलीवुड का मकड़ी जाल बिछा हुआ है यह लूट का मकर जल केवल एक ही स्तर पर नहीं और एक ही प्रकार का नहीं होता बल्कि जिलों की इकाइयों में बैठे सीएमएचओ द्वारा निजी चिकित्सा संस्थानों नर्सिंग होम्स क्लीनिक को भी बीमारों की चिकित्सा प्रसूति के नाम पर उनको निजी क्षेत्र में चलने वाले व चलाने का पंजीयन से लेकर आने को सड़कों का भुगतान सीएमएचओ हर महीने करता है।

यह हाल पूरे मध्यप्रदेश का है और यही कारण है कि सूचना के अधिकार में बैठे अधिकांश जिला चिकित्सा अधिकारी जानकारी देने से बचते हैं जबकि वह जानकारी धारा 4 के 25 बिंदुओं के अंतर्गत समीर अपनी साइटों पर डाली जानी चाहिए थी परंतु सीटों पर खोलकर देखने के बाद में उसमें जनधन के उपयोग से खरीदी गई सामग्री के बिलों की प्रशन भुगतान की प्रतियां आवंटन के बारे में कुछ नहीं डर जाता है।

यहां तक की इन हरामखोरों ने प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों से लेकर तहसील स्तर के चिकित्सालय एवं से जिला चिकित्सालय चिकित्सा महाविद्यालय के डॉक्टर अधिकारियों कर्मचारियों तक के नाम और नंबर भी नहीं डाले हैं ताकि उनसे कोई बातचीत नहीं कर सके जबकि चिकित्सा विभाग में सभी चिकित्सा केदो पर बैठे सभी डॉक्टरों के नाम नंबरडाले जाने चाहिए ताकि आसानी से बीमार व्यक्ति उनसे संपर्क कर चिकित्सा के संबंध में जानकारी ले सकें दूसरी तरफ अधिकांश चिकित्सा महाविद्यालयों जिला चिकित्सालय अप चिकित्सालयों से प्राथमिक चिकित्सा केदो तक के कार्यरत सभी डॉक्टर जो की 20% कुल वेतन का नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस सरकार से लेकर भी निजी स्तर व क्षेत्रों में अपनी सेवाएं देकर भारी मोटी कमाई करते हैंऔर इस सच को जानने के लिएपूरे प्रदेश की सभी स्वास्थ्य विभाग केसभी डॉक्टरों की मोबाइल की रिकॉर्डिंग से सच जाना जा सकता है। चिकित्सा महाविद्यालय में किस प्रकार की लूट की जा रही है खरीदी के नाम पर उसका एक छोटा सा नीचे उदाहरण दिया जा रहा है।

बेशक चिकित्सा क्षेत्र में भी शासकीय, म प्र कर्मचारी राज्य बीमा निगम के चिकित्सालयों चिकित्सा महाविद्यालय में भी पूरे प्रदेश भर में न केवल खरीदी बल्कि चिकित्सा में भी चारों तरफ दलालों का बोलबाला है जो एंबुलेंस से लेकर सरकारी दवाइयां चिकित्सा चिकित्सा प्रमाण पत्र भारती इलाज के साथ शासकीय मिलने वाले अनु को क्षेत्र में अनुदान आदि में भारी कमीशनखोरी करते रहते हैं इसीलिए अधिकांश जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य कार्यालयों में बैठे डॉक्टर अधिकारी कर्मचारी सूचना के अधिकार में जानकारी मांगने परजो कि उन्हेंस्वयं सूचना अधिकार अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गतवर्णित 25 बिंदुओं मेंअपलोड करनी चाहिए थी आप लोग तो की ही नहीं गई उसमें भी भारी जालसाजियां हैं साथ ही मांगने पर सीडी में देने की अपेक्षा हजारों से लेकर लाखों रु तक के फोटोकॉपी के बिनाधारा 7 के 3 ए बी बिंदुओं की जिसमें कहा गया हैकी पूरी तरीके से सही आंकलन कर शुल्क की मांग की जानी चाहिए।

आवेदकों को डराने हजारों से लेकर लाखों रू का मांग पत्र बना देते हैं। जो उनके भ्रष्टाचार जालसाजी और लूट की कहानी को स्वमेव प्रदर्शित कर देता है।

28 हजार का टेनेक्टिप्लेस इंजेक्शन 36 हजार में और 150 रु. का स्पाइरोमीटर 750 में खरीद रहे

मेडिकल कॉलेज में बल्क में खरीदी दवाओं के रेट रिटेल स्टोर्स में सिंगल के दाम से भी ज्यादा

एमजीएम मेडिकल कॉलेज के अस्पतालों में दवाई, इंजेक्शन से लेकर बैंडेज तक की खरीदी रिटेल रेट से कई गुना अधिक दाम में की जा रही है। भास्कर ने शहर के कई मेडिकल स्टोर्स पर विभिन्न तरह के सिंगल आयटम के रेट लिए जो जैनेरिक दवाओं की बल्क खरीदी से भी काफी कम हैं। सबसे अधिक खरीदी सुपर स्पेशियलिटी (एसएस) में की जा रही है।

दिल के मरीज को लगने वाला टेनेक्टिप्लेस इंजेक्शन 28 हजार रुपए में मिल रहा है लेकिन कॉलेज के अस्पताल इसे निजी संस्था (अमृत फॉर्मेसी) से 36 हजार में खरीद रहे हैं। इसी तरह बोन मेरो ट्रांसप्लांट के मरीजों को लगने वाला एटीजी इंजेक्शन 19,400 में मिल रहा है जिसकी खरीदी 22,069 रु. में की जा रही है। कई अन्य सामग्री चार से 16 गुना दाम में खरीदी जा रही है।

डीन द्वारा लोकल पर्चेस का टेंडर नहीं करने व रेट कॉन्ट्रैक्ट से इंप्लांट वाले आयटम हटा देने से हर महीने लाखों रुपए की चपत लग रही है। भंडार क्रय नियम के अनुसार गॉज स्वॉब और बैंडेज पॉवर लूम से ही लेना चाहिए, लेकिन अस्पताल इसे अमृत फार्मेसी से खरीद रहे हैं।

ब्लड बैग के लिए चार गुना तो गॉज स्वॉब पैकेट के 16 गुना अधिक चुकाए

सामग्री	बाजार मूल्य	खरीदी की कीमत
टेनेक्टिप्लेस इंजेक्शन	28,000	36,000
स्पाइरोमीटर	150	750
एटीजी इंजेक्शन	19,400	22,069
ब्लड बैग (सिंगल पीस)	210	850
बैंडेज रिटेल में	84	350
गॉज स्वॉब पैकेट	90	1600
कॉर्डिएक इंप्लांट	10-50 हजार	30,000
अन्यूरिजम क्लिप	25-30 हजार	50-60 हजार

3 तरह के टेंडर से की जाती है खरीदी

नियमानुसार हर खरीदी मेडिकल कॉर्पोरेशन के टेंडर से करना होती है। जो आयटम कॉर्पोरेशन के टेंडर में नहीं होते हैं, उनके लिए रेट कॉन्ट्रैक्ट (आरसी) होते हैं। इसमें जो सामग्री नहीं मिलती हैं उनके लिए लोकल पर्चेस (एलपी) का टेंडर निकाला जाता है। अंत में जो सामग्री तीनों जगह उपलब्ध नहीं होती है उसे अनुबंध के मुताबिक अमृत फॉर्मेसी से लेना होता है।

कॉन्ट्रैक्ट तीन बार बढ़ाया, वह भी खत्म पर खरीदी जारी

अमृत फॉर्मेसी से कॉन्ट्रैक्ट दिसंबर 2022 में तीसरी बार जून 2023 तक बढ़ाया। नियमानुसार पुराने कॉन्ट्रैक्ट को दो बार से अधिक नहीं बढ़ा सकते। जून में एग्रीमेंट खत्म होने के बाद भी यहां से खरीदी जारी है।

भारत में लगाये जा रहे टीको पर विस्तृत अध्ययन क्यों नहीं

क्या पूरे देश में 140 करोड़ WHO के ही रहेंगे गुलाम

देश की प्राकृतिक आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति का संवर्धन अध्ययन विकास क्यों नहीं किया जा रहा

हमारे देश के प्राचीन आयुर्वेद में बच्चों को स्वस्थ और जीवन पर्यंत अनेकों घातक रोगों से लड़ने निरोगी व मजबूत बनाए रखने के लिए पैदा होने के साथ ही 4-5 साल की उम्र तक लगातार जायफल, खारक, केसर, बादाम, आमाहल्दी, काला नमक, जावित्री, हींग, हरड़, सुहागा व अनेकों आयुर्वेदिक औषधियों की अलग अलग आयु वर्गों व वजन के हिसाब से घुट्टी देने का प्रचलन था। जो हमारी नानी दादियां अपनी बहू बेटियों को किसको किस मात्रा में किस तरह से कितनी बार घिस, काट, पीस, गर्म करके किस मौसम में किस बीमारी, शारीरिक परेशानी में किस के साथ, मिला कर कितनी मात्रा में कितने बजे देना है। सब समझाती, बताती थीं। वही हाल बदन पर मालिश करने में किस तेल में क्या-क्या कितना मिला कैसे तेल को तैयार कर कितनी कैसे कहां मालिश करनी है। शास्त्रों वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ी घर की बुजुर्ग महिलाएं अपनी बहू बेटियों को समझाया बताया करती थी ताकि बच्चे निरोगी सुदृढ और शारीरिक व मानसिक रूप से जीवन पर्यंत मजबूत बने रह सकें परंतु आधुनिकता के लिवास में यह सब भुला दिया गया और उसकी कमजोरी का फायदा उठाकर अमेरिकी विश्व घटक संगठन यूनिसेफ हमारे यहां टीके व औषधीयों का परीक्षण के बहाने प्रयोग व मोटी करते रहे। इसके साथ ही भारत सरकार बहुराष्ट्रीय कंपनियों के सारे पर नाच कर अपने ही देश के आयुर्वेद के ज्ञान को द्वितीय तृतीय स्तर पर रख पूरक के रूप में उपयोग करते रहे।

परंतु स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ पूरी संसद में छल बल दल धन और जालसाजी से पहुंचे जाहिल अपराधियों गुंडे बदमाशों को इन सब से क्या लेना देना था उन्हें तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के सारे पर नाच करउनका माल खरीदने में मोती कमीशन से मतलब रहता है। इसलिए वह उनके इसारे पर नाच कर विश्व घातक संगठन और उसको धन देने वाली कंपनियों के माल माल जिसमें विभिन्न प्रकार के सैकड़ो टीके जिसमें डिप्थीरिया निमोनिया पोलियो हेपेटाइटिस रूबेला चेचक रेबीज रेबीज मंप्स आदि प्रमुख हैं।

विश्व घातक संगठन और उसके अनुषांगिक संगठन यूनिसेफ के इशारे पर देश के 10 करोड़ बच्चों को लगाई जा रही नीचे दी जा रही टीकों की सूची जबकि इन टिकों के बारे मेंऑल इंडिया इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज आईसीएमआर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन किसी ने कोई गहराई से अध्ययन नहीं किया जो की विदेश की रिपोर्ट में यह सामने आया कि इन टिकों को लगाने के बाद में भी यथार्थ में बीमारियां समय पौष्टिक भोजन मिलने के कारण कम हुई है याउन टिकों का सचमुच कोई प्रभाव हुआ है जो कि विदेशी रिपोट्र्स में बताया गया कि अधिकांश ठीक है बकवास है और बहुत मजबूती के साथ इनके दागों को स्वीकार नहीं किया जा सकता जबकि स्वयं एक शासकीय 40 वर्ष के अनुभवी डॉक्टर से बात करते समय उन्होंने एक महत्वपूर्ण तथ्य इस एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति का मुझे बताया जो बहुत ही चौंकाने और डरने वाला थाउन्होंने बतायाकिसी चिकित्सक से बात करते समय किसी पत्रकार ने पूछा कि आपका यह एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति विज्ञान है या कला, की जवाब में उस चिकित्सक ने कहा कि यह मनुष्य को जीवन बचाने की कला है और संभावनाओं का सिद्धांत है अर्थात जीवन बचाने की कला तो हर मनुष्य ही नहीं धरती के हर प्राणी को प्रकृति प्रदत्त है। पर इस तत्व के उस रोग पर तत्व का प्रयोग करने पर वह स्वस्थ हो गया तो ठीक है नहीं हुआ मर गया तो भी ठीक है संभावना ही तो है।

जबकि आयुर्वेद के साथ यूनानी होम्योपैथी में प्रकृति के हर तत्व का न केवल मनुष्य वरन अन्य प्राणियों के जीवन, बीमारियों के साथ उसकी मनः स्थिति पर क्या असर पड़ेगा, की विस्तृत व्याख्या करता है, ये यह सब जीवन की प्राचीन चिकित्सा पद्धतियां संभावनाओं का विज्ञान या कला नहीं।

देश की सरकारों को चाहिए कि हमारे स्कूलों में ही तीसरी क्लास से छठवीं क्लास तक केवल देश को निरोगी और स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए घर में रखें 20 से ज्यादा मसालों, खाद्य पदार्थों फल फूलों का चिकित्सीय मूल्य वह उसकी उपयोग करने के तरीकों को आयुर्वेद के अनुसार शिक्षा में पढ़ने की व्यवस्था करें तो छात्रों की अगली पीढ़ी अगले 10 साल के बाद में अपने घर के रख मसाले से ही अपनी शारीरिक मानसिक बीमारियों, विकारों को दूर करने में सक्षम हो जाएगी जिससे विदेशी औषधीयों, टीकों, उपकरणों का आयात पर लगने वाला, सरकार का खर्च होने वाला धन कल लाखों करोड़ों बचाने के साथ देश की जनता पर किए जा रहे ड्रग ट्रायल से होने वाली मौतों और अन्य परेशानियों से बचने का अवसर एलोपैथी कसाई डॉक्टरों की अनावश्यक चिकित्सा परहोने वाले खर्च से बचाव स्वयं जनता को मिल जाएगा। इसको सरकार व जनता गहराई से समझे।

Age	The National immunization schedule	2014 Indian Academy of Pediatrics
0 (at birth)	BCG, OPV0, HBV0*	BCG, OPV0, HBV1
6 weeks	DTwP1, OPV1, HBV1*, HiB1*	DTwP1, IPV1, HBV2, HiB1, Rotavirus 1, PCV1
10 weeks	DTwP2, OPV2, HBV2*, HiB2*	DTwP2, IPV2, HiB2, Rotavirus 2, PCV2
14 weeks	DTwP3, OPV3, HBV3*, HiB3*	DTwP3, IPV3, HiB3, Rotavirus 3, PCV3
6 months	-	OPV1, HBV3
9 months	Measles, Vitamin A	OPV2, MMR1 (9-12 months) typhoid conjugate vaccine
12 months	-	HAV1
15 months	MMR*	MMR2, varicella 1, PCV booster
16-24 months	DTwP B1, OPV B1, Vitamin A2, Japanese Encephalitis*	16-18 months DTwP B1/DTaP B1/IPV B1, HiB B1 (18 months) HAV2
2 years	-	Typhoid booster
5 years	DTwP B2	4-6 years DTwP B2/DTaP B2, OPV3, varicella 2, typhoid booster
10 years	TT	10-12 years Tdap/Td, HPV
16 years	TT	

*Implemented in selected states, districts, and cities. B1: First booster dose, B2: Second booster dose, BCG: Bacillus Calmette Guerin, DT: Diphtheria toxoid and tetanus toxoid, DTwP: Diphtheria, tetanus toxoid, whole cell pertussis, DTaP: Diphtheria, tetanus toxoid, acellular pertussis, HAV: Hepatitis A vaccine, Td: Tetanus toxoid with reduced diphtheria, Tdap: Reduced diphtheria toxoid and acellular pertussis vaccine, HBV: Hepatitis B vaccine, HiB: *Haemophilus influenzae* b, HPV: Human papillomavirus vaccine, MMR: Measles, mumps and rubella, OPV: Oral poliovirus vaccine, PCV: Pneumococcal conjugate vaccine, TT: Tetanus toxoid

टीकाकरण और इसके प्रतिकूल प्रभावः वास्तविक या कथित

समाज को जोखिम को संभावित दीर्घकालिक प्रभाव से जोड़ने के तरीकों के बारे में सोचना चाहिए

टीकों को अचानक शिशु मृत्यु सिंड्रोम, 1 बाल चिकित्सा अस्थमा, 2 ऑटिज़्म, 3 सूजन आंत्र रोग, 4 और स्थायी मस्तिष्क क्षति से जोड़ा गया है। 5 हाल ही में अमेरिकी शोधकर्ताओं ने सुझाव दिया है कि जन्म के 28 दिनों के बाद टीकाकरण टाइप 1 (ऑटोइम्यून) मधुमेह को प्रेरित कर सकता है। अतिसंवेदनशील व्यक्तियों में मेलिटस।5 इस वर्ष की शुरुआत में अमेरिकी मीडिया द्वारा उछाले गए इस सिद्धांत के कारण बचपन के नियमित टीकाकरण में विश्वास कम हो सकता है। मई में कई संस्थानों (नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इंफेक्शियस डिजीज, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूके के स्वास्थ्य विभाग सहित) ने संभावित कारण के साक्ष्य का आकलन करने के लिए यूएस नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ में एक कार्यशाला प्रायोजित की। जोड़ना।

इम्यूनोलॉजिस्ट, मधुमेह विशेषज्ञ, महामारी विज्ञानी, नीति निर्माता और पर्यवेक्षकों ने दो दिनों तक उपलब्ध साक्ष्यों पर बहस की और निष्कर्ष निकाला कि यह टीकाकरण और टाइप 1 मधुमेह की शुरुआत के बीच किसी कारणात्मक संबंध का समर्थन नहीं करता है। परिकल्पना का परीक्षण करने के लिए कुछ अल्पकालिक और दीर्घकालिक अवलोकन संबंधी अध्ययन वर्तमान में चल रहे हैं। हालाँकि, 1985-76 में फिनलैंड में हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी के खिलाफ टीके के एक बड़े यादृच्छिक नियंत्रित परीक्षण के परिणामों का तुओमीलेहतो एट अल द्वारा पुनः विश्लेषण किया गया और मधुमेह मेलेटस की घटनाओं और अनुसूची में एक और एंटीजन के शामिल होने के बीच कोई संबंध नहीं दिखाया गया।, समय की

परवाह किए बिना (अप्रकाशित डेटा)। फ़िनिश मधुमेह रजिस्टर के साथ एक्सपोज़र (इस मामले में शिशु टीकाकरण या प्लेसीबो प्रशासन) पर व्यक्तिगत जानकारी को संभावित रूप से जोड़ने से डेटा पुनर्विश्लेषण संभव हो गया था।

बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने के लिए छह आयुर्वेदिक जड़ी-बूटियाँ

आपके बच्चे की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने से न केवल उन्हें इस महामारी से निपटने में मदद मिल सकती है, बल्कि लंबे समय में यह अत्यधिक फायदेमंद साबित होगा। भारत इस समय एक भीषण महामारी से लड़ रहा है, जो पहली लहर के विपरीत, बच्चों को भी प्रभावित कर रही है। इसलिए, उनके आहार, फिटनेस और प्रतिरक्षा स्तर का अतिरिक्त ध्यान रखना बेहद जरूरी है। जहां स्वच्छ भोजन, नियमित व्यायाम और कुछ खाद्य पदार्थ प्रतिरक्षा को बढ़ावा देने में मदद करते हैं, वहीं कुछ आयुर्वेदिक जड़ी-बूटियां भी हैं जो बेहद स्वस्थ मानी जाती हैं। 'कौमरभृत्य आयुर्वेद की शाखा है जो बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता और कल्याण से संबंधित है। यह उचित पाचन, पोषण, प्रतिरक्षा और चयापचय सहित बाल स्वास्थ्य के सभी प्रमुख पहलुओं को बनाए रखने पर केंद्रित है' माहेश्वरी फार्मास्यूटिकल्स इंडिया लिमिटेड के संचालन निदेशक निखिल माहेश्वरी ने कहा। इसके अलावा, उन्होंने कहा कि आयुर्वेद द्वारा परिभाषित पांच विशिष्ट जड़ी-बूटियाँ हैं जो प्रतिरक्षा में सुधार करने में मदद करेंगी। एक नजर डालें-

तुलसी

यह अपने असंख्य लाभों और असाधारण औषधीय गुणों के लिए जाना जाता है। विटामिन सी, ए और के से भरपूर तुलसी को अक्सर जड़ी-बूटियों की रानी कहा जाता है। तुलसी बुखार को कम करने में मदद करती है और सामान्य सर्दी या खांसी के लिए एक उत्कृष्ट उपाय है। इसके अलावा, यह अच्छे हृदय स्वास्थ्य में भी मदद कर सकता है।

हल्दी

इसे हल्दी के नाम से भी जाना जाता है, यह हर भारतीय घर का मुख्य भोजन है। खाने का स्वाद बढ़ाने के अलावा हल्दी अपने एंटी-इंफ्लेमेटरी गुणों के लिए भी जानी जाती है। 'एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर, हल्दी हृदय स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करती है, हृदय संबंधी बीमारियों के खतरे को कम करती है और यहां तक कि इसमें कैंसर विरोधी गुण भी होते हैं। इसका व्यापक रूप से त्वचा की देखभाल में और कटने और घावों के उपचार के रूप में भी उपयोग किया जाता है क्योंकि यह त्वचा को ठीक करने और आराम देने में मदद करता है, 'उन्होंने कहा।

अश्वगंधा

'एक प्राचीन औषधीय जड़ी बूटी, अश्वगंधा न केवल शारीरिक बीमारियों को ठीक करने में बल्कि मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए भी जानी जाती है।' प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने के अलावा, यह मांसपेशियों को बढ़ाने और मस्तिष्क की कार्यक्षमता को बढ़ाने के साथ-साथ ताकत भी प्रदान करता है।

आंवला

विटामिन सी का एक समृद्ध स्रोत, आंवला सामान्य सर्दी, खांसी और गले की खराश को दूर रखने में मदद करता है। उन्होंने बताया, 'प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने वाले, आंवले में प्रचुर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और इसका उपयोग स्वस्थ बालों, मधुमेह से राहत और यहां तक कि दृष्टि में सुधार के लिए भी किया जाता है।'

गिलोय

'टीनोस्पोरा कॉर्डिफ़ोलिया के रूप में भी जाना जाने वाला गिलोय अपने औषधीय गुणों और उच्च पोषण मूल्य के लिए जाना जाता है। इसका उपयोग मुख्य रूप से शरीर में प्रतिरक्षा विकसित करने के लिए किया जाता है और एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है, 'उन्होंने कहा कि यह शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने के लिए भी जाना जाता है और तेज बुखार और खांसी के मामले में इसे लिया जा सकता है।

जायफल

खाने में इस्तेमाल होने वाला जायफल एक मसाला है, जो स्वाद और सुंगध से भरपूर होता है. कई नुस्खों में भी जायफल का इस्तेमाल किया जाता है. बच्चों को सर्दी जुकाम होने पर दादी-नानी जायफल खिलाने की सलाह देती हैं. इससे अपच, मुंह के छाले और पेट की समस्याएं दूर होती हैं. जायफल एंटीबैक्टीरियल और एंटीबायोटिक गुणों से भरपूर होता है. इसे खाने से सीजनल बीमारियां दूर रहती हैं.

जॉन्स हॉपकिन्स यूनिवर्सिटी में इंस्टीट्यूट फॉर वैक्सीन सेफ्टी के प्रमुख नील हैल्सी ने हालिया वैक्सीन संबंधी डर की सामान्य विशेषताओं का सारांश दिया:

आमतौर पर अज्ञात या अस्पष्ट एटियलजि की बीमारी या स्थिति के साथ एक आकस्मिक संबंध का दावा किया जाता है।

एसोसिएशन का दावा एक अन्वेषक या जांचकर्ताओं के एक समूह द्वारा किया जाता है। इस संबंध की पुष्टि साथियों या बाद के शोधों द्वारा नहीं की गई है। ये दावे जनता के विश्वास की हानि और बच्चों को टीका लगाने से इनकार करने से होने वाले संभावित नुकसान की कोई स्पष्ट चिंता के बिना किए गए हैं।

इसके अतिरिक्त, बाद के अध्ययनों के निष्कर्ष जो मूल दावे की पुष्टि करने में विफल रहते हैं, उन्हें कभी भी 'मूल' निष्कर्ष को प्रचार नहीं मिलता है; इस प्रकार जनता को कभी भी संतुलित दृष्टिकोण नहीं मिल पाता।

अब इस बारे में गहराई से सोचने का समय आ गया है कि समाज टीकाकरण के संभावित दीर्घकालिक और दुर्लभ प्रतिकूल प्रभावों के कठिन मुद्दे से कैसे निपट सकता है। इस मुद्दे पर ध्यान कम होने की संभावना नहीं है, क्योंकि नए और बेहतर टीके तैयार किए जा रहे हैं और प्रभावी और सुरक्षित हस्तक्षेप के बारे में जनता की उम्मीदें बढ़ रही हैं। दुर्लभ और दीर्घकालिक प्रभावों पर डेटा का पहला स्पष्ट स्रोत वैक्सीन का मूल नैदानिक परीक्षण है, जिसमें डबल ब्लाइंड यादृच्छिक हथियारों में से एक में घटनाओं की घटनाओं का प्रत्यक्ष अवलोकन होता है। लेकिन, प्रारंभिक परीक्षण, आमतौर पर पंजीकरण के लिए आयोजित किए जाते हैं, बहुत छोटे और बहुत छोटे होते हैं। इसके अतिरिक्त, प्रतिकूल प्रभावों का मूल्यांकन संभवतः एक या अधिक हस्तक्षेप हथियारों की घटनाओं की प्लेसबो बांह के साथ तुलना करके सबसे अच्छा किया जाता है, इस प्रकार अवलोकन को परीक्षणों तक सीमित कर दिया जाता है। नए या आंशिक रूप से परीक्षण किए गए टीके जिनके लिए प्लेसबो आर्म नैतिक रूप से स्वीकार्य है।

एक संभावित समाधान दुर्लभ और दीर्घकालिक प्रतिकूल प्रभावों का पता लगाने के लिए परीक्षणों की अवधि और शक्ति को बढ़ाना हो सकता है। हालांकि, लागत के अलावा, टीके की अल्पकालिक सुरक्षा और प्रभावशीलता दिखाए जाने के बाद संभावित दुर्लभ और दीर्घकालिक प्रभावों का पता लगाने के प्रयास में गैर-प्रतिरक्षित समूह के साथ परीक्षण जारी रखने में प्रमुख नैतिक समस्याएं हैं।

केस-नियंत्रण अध्ययन और केस श्रृंखला का उपयोग किसी एसोसिएशन की संभावना को परिभाषित करने में सहायक है, लेकिन कई अज्ञात पूर्वाग्रहों की संभावित उपस्थिति को देखते हुए, ऐसे अध्ययन सुरक्षा मूल्यांकन के लिए आवश्यक जोखिम के अनुमान की अनुमति नहीं देते हैं। किसी भी संभावित दृष्टिकोण के साथ एक अतिरिक्त समस्या यह है कि कुछ प्रतिकूल प्रभाव वैक्सीन के विकास, विपणन और पंजीकरण के वर्षों बाद ही ज्ञात हो जाते हैं, जिससे 'डेटा ड्रेजिंग' ही एकमात्र तरीका बन जाता है जिससे उन्हें देखा जा सकता है और बाद में पहचाना जा सकता है। डेटा ड्रेजिंग अप्रभावी होने और अप्रत्याशित संघों का आकलन करने में असमर्थ होने की संभावना है, जो समय-समय पर होने की संभावना है।

दुविधा से बाहर निकलने का एक तरीका टीकाकरण के व्यक्तिगत जोखिम को बाद के जीवन में संभावित प्रतिकूल घटनाओं से जोड़ना हो सकता है, जैसे कि मूल हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा प्रकार बी परीक्षण डेटा के तुओमिलेहतो एट अल द्वारा पुनर्विश्लेषण।

यह उत्पन्न किसी भी परिकल्पना के परीक्षण के लिए ऐतिहासिक नियंत्रण से जुड़े पूर्वव्यापी एक्सपोज़र समूहों के निर्माण की अनुमति देगा। इस दृष्टिकोण के लिए व्यक्तिगत टीकाकरण डेटा तक पहुंच और बाद के जीवन में व्यक्तियों की पहचान करने और उनका पता लगाने की क्षमता की आवश्यकता होगी। चूंकि अधिकांश टीकाकरण कार्यक्रम अलग-अलग देशों में अलग-अलग होते हैं।

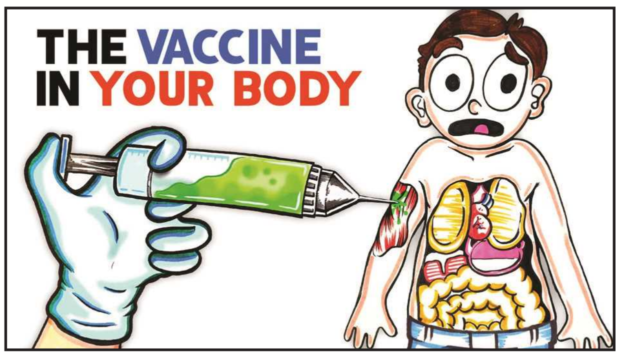

ईवीएम हटाओ लोकतंत्र व देश बचाओ

पेज 1 का शेष

चुनाव परिणामों से निम्न बातें साफ हो गई हैं:

- नौकरी व शिक्षा की जरूरत नहीं, भर्ती में घोटाले और भ्रष्टाचार चाहिए।
- जिंदगी भर नौकरी करने और रिटायरमेंट के बाद पत्नी की सुरक्षा के लिए OPS नहीं NPS चाहिए।
- धार्मिक उन्माद और महिला असुरक्षा चाहिए।
- युवाओं को परमानेंट नौकरी नहीं अग्निवीर चाहिए, बेकारी, बेरोजगारी की मार चाहिए।
- भ्रष्टाचार युक्त माहौल और भ्रष्ट नेता चाहिए।
- ओबीसी सुरक्षा नहीं, दलितों पर अत्याचार चाहिए।
- किसानों के लिए MSP, खाद, बीज, कीटनाशक, पशु, बिजली, बीमा जैसी चीजें नहीं चाहिए।
- मोहब्बत नहीं, नफरत चाहिए।
- काम की बात करने वाले नेता नहीं, जुमलेबाज चाहिए।
- गांधीवादी सोच नहीं, गोडसे के संस्कार चाहिए।
- देश में नए संस्थान खोलने वाली नहीं, बेचने वाली सरकार चाहिए।
- स्वतंत्र पत्रकारिता नहीं, गोदी मीडिया चाहिए।
- कमाई का जरिया नहीं, मुफ्तखोरी व गुलामी चाहिए।
- अंधभक्ति अब समझ में आएगी लोगों को!
- सबका कल्याण हो ऐसी आशा करता हूं!

ईवीएम का रोना कौन रोता था?

याद रहे '2009 में बीजेपी ही ईवीएम का विरोध करती थी. भाजपा नेता जीवीएल नरसिम्हा राव ने 'डेमोक्रेसी एट रिस्क' नाम से किताब भी लिखी थी. उसे पुरस्कृत किया गया था और वह सांसद भी बने. खुद लालकृष्ण आडवाणी ने किताब की प्रस्तावना लिखी थी.

याद रहे कि ईवीएम का विरोध करने वाली सबसे पहली राष्ट्रीय पार्टी भाजपा ही थी. साल 2009 के आम चुनाव में मिली हार के बाद भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने ईवीएम पर सवाल उठाए थे. 2010 तक पार्टी के तत्कालीन प्रवक्ता जीवीएल नरसिम्हा राव ने यह साबित करने के लिए कि ईवीएम से छेड़छाड़ संभव है, पूरी की पूरी किताब लिख डाली. किताब का नाम रखा- 'डेमोक्रेसी एट रिस्कः कैन वी ट्रस्ट ऑर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन'

इस किताब की प्रस्तावना आडवाणी ने लिखी. किताब के भीतर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू का भी संदेश छपा... सुब्रमण्यम स्वामी जैसे वरिष्ठ भाजपा नेताओं ने विशेषज्ञों की मदद से ईवीएम के खिलाफ देशव्यापी अभियान छेड़ दिया था. हालांकि अब भाजपा ईवीएम का समर्थन करती है.

2014 से पहले खुद मोदी ने भी अपने भाषण में कहते थे कि अमेरिका जैसे विकासशील देश में आज भी भी बैलट पेपर से ही चुनाव होता है..!

ईवीएम मशीन वोट चोरी करती है व इससे फ्री फेयर एन्ड ट्रान्सप्रेन्ट अर्थात स्वतंत्र निष्पक्ष व पारदर्शी चुनाव असंभव है - सुब्रमण्यम स्वामी भाजपा नेता ने यह बात सुप्रीम कोर्ट में साबीत करके बताई ओर सुप्रीम कोर्ट ने माना भी है (8 अक्टूबर 2013)

तब ईव्हीएम की वोट चोरी रोकने के लिये ग्यारह लाख आठ हजार करोड रूपये लगा कर वीवीपैट मशीन को लगाया गया. वीवीपैट की पर्चियों की गणना नही करने की वजह से यह चुनाव परिणाम संदिग्ध है.

ईवीएम के मायाजाल में छिपा संघ और जनता का विरोध

भाजपा की जीत के पीछे कुछ अनसुलझे सवाल और रहस्य जनता के मन में छाए हुए हैं, जहां वर्तमान विधानसभा चुनाव में बीजेपी की बंपर जीत से जहां मीडिया, जनता और स्वयं बीजेपी के जमीनी नेता भी आश्चर्यचकित है, आखिर कैसे ये चमत्कार हो गया...?

संघ ने हर प्रदेश में भाजपा के गुण्डातत्व और स्थानीय नेताओं का खुलकर किया विरोध

ईवीएम की आड़ में भाजपा संघ की मेहनत का ढिंढोरा पीट रही है जबकि संघ ने मप्र, राजस्थान छत्तीसगढ़ सहित भाजपा नेताओ का विरोध किया, देवास में भी हिंदुत्व की छवि लिए कांग्रेस के युवा प्रत्याशी प्रदीप चौधरी का खुलकर समर्थन किया। जबकि देवास सांसद ने परदे के पीछे प्रदीप की सहायता जगजाहिर है।

भाजपा की हार की पटकथा संघ ने लिखी....

हिदुत्व के असली मुद्दों से भाजपा भाग रही, जिसके विपरीत आज प्रदेश में भाजपा का भ्रष्टाचार और कानून अव्यवस्था का बोल बाला है। इस बार सभी पूर्व रुझानों में कांग्रेस की सरकार बनती नजर आ रही थी, संघ और अपने नेताओं की गुटबाज़ी से भाजपा परेशान थी। संघ से नाराज स्वयं सेवकों ने भी भाजपा के खिलाफ दमदारी से प्रचार किया।

मोदी और शाह ने जमाया ईवीएम का मायाजाल

भाजपा के अंदरूनी सूत्र बताते हैं कि सारा मामला ईवीएम में सेट है, किसको जिताना है किसको हराना है इसकी पटकथा दिल्ली में लिखी गई, शिवराज के चेहरे को जनता ने नकारा अब 2024 के पहले फिर हार का तमगा मोदी अपने माथे पर नही लेना चाहते थे, इसीलिए गोदी मीडिया को साथ लेकर रचा ईवीएम का मायाजाल।

कांग्रेस की तेलंगाना में जीत दिखावा, असल में कांग्रेस चार राज्यों में सरकार बना रही थी....

तेलंगाना में कांग्रेस सरकार बनी या यूं कहे की ईवीएम से छेड़छाड़ नहीं की क्योंकि कि एक जीत के पीछे 3 राज्यों में की गई बदमाशी भी जायज़ लगे। एक राज्य गंवाने की शर्त पर 3 बड़े हिंदी भाषी राज्य भाजपा ने हथिया लिए। अब तेलंगाना की जीत पर कांग्रेसियों के मुंह पर ताले भी लग गए और कोई ईवीएम के मायाजाल की बात नही कहेगा।

राहुल गांधी की छवि लगातार सुधर रही, 2024 की लड़ाई आसान नहीं

राहुल गांधी की छवि में भारत जोड़ो यात्रा के बाद से लगातार सुधार रही है, मीडिया और जनता मजबूत होते एक नए राहुल गांधी की ओर आकर्षित हो रही है, इसी का डर मोदी और भाजपा को सता रहा है रोज नई इवेंट के सहारे मोदी अपनी लोकप्रियता को बढ़ाने की जुगत में थे लेकिन लगातार उनका ग्राफ गिरता जा रहा था, इसलिए ईवीएम का स्वांग रचा गया।

गोदी मीडिया ने लगाया तड़का, जनता को मायाजाल में उलझा कर भाजपा की जीत को सही बनाने का स्वांग रचा गया

सवाल - नरोत्तम को क्यों हराया....?

जवाब - क्योंकि वे खुद को मुख्यमंत्री का दावेदार मानने लगे थे, उनकी कार्यशैली से भाजपा और संघ नाराज था इसलिए हार के लिए सेट थी ईवीएम

सवाल - इमरती देवी को क्यों हराया..?

सिंधिया समर्थकों में कई नेताओं को हराने के लिए सेट थी ईवीएम जिसकी पूरी जानकारी सिंधिया को भी थी, दरअसल उनके कई नेता खुद सिंधिया की गले की फांस बन गए थे इमरती सहित कई और हारे नेताओ के आने से भाजपा और सिंधिया की छवि टूट रही थी। इसलिए हार के लिए सेट थी ईवीएम।

कांग्रेस के दिग्गज नेताओं की तालाबंदी ताकि फिर कांग्रेस मप्र, राजस्थान, छग में खड़ी ना हो

2024 के मोदी मिशन में कमलनाथ सरकार रोड़ा थी, कांग्रेस के 2 और राज्यों में जहां कांग्रेस की सरकार थी यानी छत्तीसगढ़ और राजस्थान। दोनो राज्यों में कांग्रेस ने बेहतर काम किया जनता का बढ़ता रुझान देख दोनो राज्यों की कहानी ईवीएम ने लिखी। 3 राज्यों में अप्रत्याशित नतीजे निश्चित तौर पर किसी षड्यंत्र की ओर इशारा कर रहे हैं। दिग्गज कांग्रेस नेताओ को ईवीएम ने हराया, जबकि भाजपा के कई नेता भारी विरोध के बावजूद जीते।

नतीजे के बाद जनता बस यही बोल रही है हमने तो कांग्रेस को वोट दिया...लेकिन हमारे साथ फिर धोखा हुआ... फिर वही पेट्रोल बिजली बिल की लूट, महंगाई बेरोजगारी...

ये ना भाजपा सरकार है ना हमारे मन में मोदी.... ये आज के कलयुग में 'ईवीएम सरकार' है

कौन लिखता है evm का सोर्स कोड ? आखिर इससे जुडी जानकारियों को बाहर क्यों नहीं आने दिया जा रहा

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) में इस्तेमाल होने वाले सोर्स कोड के ऑडिट की मांग करने वाली एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर विचार करने से इनकार कर दिया।

जनहित याचिका में ईवीएम के 'सोर्स कोड' के स्वतंत्र ऑडिट की मांग की गई थी और प्रार्थना की गई थी कि ऑडिट रिपोर्ट को सार्वजनिक डोमेन में रखा जाए।

'सोर्स कोड' कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का उपयोग करने वाले प्रोग्रामर के निर्देशों और कथनों का एक 'सेट' होता है। याचिकाकर्ता सुनील अह्वा ने कहा कि ईवीएम 'सोर्स कोड' से ही चलता है और यह याचिका लोकतंत्र को बरकरार रखने के संबंध में है।

याचिकाकर्ता ने पहले 2019 के आम चुनावों से पहले इसी तरह की याचिका दायर की थी। उस समय, यह माना गया था कि आसन्न चुनावों के कारण याचिका में शामिल होना संभव नहीं था। फिर याचिकाकर्ता ने 2020 में भी इस मुद्दे पर एक जनहित याचिका दायर की थी। उन्हें ईसीआई के समक्ष प्रतिनिधित्व करने की अनुमति दी गई थी। याचिकाकर्ता ने पीठ को बताया कि ईसीआई ने उनके अभ्यावेदन का जवाब नहीं दिया, इसलिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।

सुनवाई के दौरान बेंच ने याचिकाकर्ता सुनील अह्वा से पूछा कि क्या ऐसी कोई सामग्री है जो ईवीएम मशीनों पर संदेह पैदा करती है। अह्वा ने जवाब दिया कि ईवीएम के पीछे स्रोत कोड का दिमाग है और नागरिक एक ऐसी प्रणाली के माध्यम से मतदान कर रहे हैं जिसका ऑडिट नहीं किया जाता है। उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में, ऐसी ऑडिट रिपोर्ट सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध हैं, लेकिन भारत में ईवीएम स्रोत कोड का स्वतंत्र रूप से ऑडिट नहीं किया जा रहा है या हैश फ़ंक्शन हस्ताक्षर नहीं हैं।

इस पर अदालत ने टिप्पणी की, 'यह सार्वजनिक डोमेन में नहीं होना चाहिए क्योंकि इससे खतरा हो सकता है और इसका दुरुपयोग हो सकता है।' अपने आदेश में कहा, 'वर्तमान में, याचिकाकर्ता ने यह इंगित करने के लिए रिकॉर्ड पर कोई कार्रवाई योग्य सामग्री नहीं रखी है कि चुनाव आयोग ने संवैधानिक जनादेश का उल्लंघन किया है।' सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि 'जिस तरीके से सोर्स कोड का ऑडिट किया जाना चाहिए या ऑडिट को सार्वजनिक डोमेन में रखा जाना चाहिए, वह चुनाव की अखंडता से संबंधित संवेदनशील मुद्दों पर आधारित है, जो चुनाव आयोग के पर्यवेक्षण में आयोजित किए जाते हैं।' याचिका को खारिज करते हुए आदेश दिया गया, 'ऐसे नीतिगत मुद्दे पर, हम याचिकाकर्ता द्वारा मांगे गए निर्देश जारी करने के इच्छुक नहीं हैं।'

दरअसल जो मशीन भारत में ईव्म के नाम से जानी जाती है उसे ही अंतर्राष्ट्रीय तौर पर (DRE) यानी डायरेक्ट रिकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कहा जाता है ,जो की वोट को डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी में सेव कर लेती है इसी से मिलती जुलती सब मशीन बहुत देशो में बैन की जा चुकी है

इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन सिर्फ और सिर्फ तब ही सुरक्षित है जब तक इसमें वास्तविक कोड प्रणाली इस्तेमाल की जाती है। लेकिन चौकाने वाला तथ्य ये है भारत की EVM मशीन निर्माता कंपनी BEL एंड ECIL ने ये टॉप सीक्रेट (EVM मशीन के सॉफ्टवेर कोड) को दो विदेशी कंपनियो के साथ साझा किया गया है विदेशी कंपनियों को दिया सॉफ्टवेयर भी जाहिरा तौर पर सुरक्षा कारणों से, निर्वाचन आयोग के पास उपलब्ध नहीं है.

ईवीएम माइक्रो कंट्रोलर के निर्माताओं में से एक माइक्रोचिप इंक (यूएसए) है माइक्रोचिप इंक न केवल भारतीय ईवीएम में प्रयुक्त माइक्रोचिप की आपूर्ति करता है, बल्कि माइक्रोचिप पर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम राइट भी करता है. उसके बाद इस तरह से उसकी सीलिंग की जाती है कि न तो चुनाव आयोग, न भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और न ही भारतीय कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड उसकी प्रोग्रामिंग को पढ़ सके

ईवीएम का सोर्स कोड परम गोपनीय (टॉप सीक्रेट) रखा गया है. यह इतना गोपनीय है कि चुनाव आयोग के पास भी उसकी नक़ल नहीं है. न कोई इसकी कोई ऑडिट रिपोर्ट है इस सोर्स कोड का महत्व जगज़ाहिर है, प्रोग्राम कोड को मशीन कोड में बदलने के बाद ही विदेशी चिप निर्माता को दिया जाता है, क्योंकि हमारे पास देश में सेमी-कंडक्टर माइक्रोचिप्स बनाने की क्षमता नहीं है. यहीं पर चुनाव आयोग एक भ्रामक घोषणा करता है और झूठे आश्वासन देता है, क्योंकि चुनाव आयोग जो बात नहीं कह रहा है वो यह है कि जिस प्रोग्राम कोड को बाइनरी लैंग्वेज में राईट किया गया है, उसे माइक्रोचिप विनिर्माण कम्पनियां पढ़ भी सकती हैं और उनके साथ छेड़छाड़ भी कर सकती हैं. दूसरे शब्दों में कहें, तो ये विदेशी कम्पनियां किसी विशिष्ट राजनीतिक दल के हितों के अनुरूप प्रोग्राम के साथ छेड़छाड़ कर सकती हैं.

प्रोग्राम कोड से छेड़छाड़ की संभावनाएं

मशीन बंद किए जाने के 24 घंटे बाद किसी उम्मीदवार के वोट का कुछ प्रतिशत हिस्सा किसी अन्य राजनीतिक दल के पक्ष में हस्तांतरित करना.

मतदान के बाद मशीन को फिर से चालू कर किसी उम्मीदवारों के मतों का एक प्रतिशत किसी अन्य राजनितिक दल के पक्ष में हस्तांतरित करना

वेंकटेश नायक द्वारा डाली गई आरटीआई से ईवीएम के संबंध में कई जानकारियां सामने आई हैं. इससे पता चला है कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा बनाई गईं ईवीएम और वीवीपैट में प्रयुक्त माइक्रो कंट्रोलर चिप का निर्माण अमेरिका स्थित अरबों डॉलर की कंपनी एनएक्सपी ने किया है. इन्हीं ईवीएम और वीवीपैट का प्रयोग इन चुनावों में हुआ है.

इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने माइक्रो कंट्रोलर चिप बनाने वाली कंपनी का नाम आरटीआई एक्ट के सेक्शन 8(1)(d) के तहत व्यावसायिक भरोसे का हवाला देते हुए साझा करने से मना कर दिया. माइक्रो कंट्रोलर चिप के बारे में चुनाव आयोग का कहना है कि ये वन टाइम प्रोग्रामेबल है, जबकि इसे बनाने वाली कंपनी की वेबसाइट पर लिखा है कि इसमें तीन तरह की मेमोरी एसआरएम, फ्लैश और ईईपीआरओएम का प्रयोग होता है. जानकार बताते हैं कि जिन माइक्रो कंट्रोलर चिप में फ्लैश मेमोरी का प्रयोग होता है, उन्हें वन टाइम प्रोग्रामेबल नहीं कहा जाता है. इतना सब होने पर भी पता नहीं क्यों इस मैटर को दबाया जा रहा है इसलिए आवश्यक है सबसे पहले ईवीएम मशीन हटाओ। इसलिए सभी विपक्षी दल और जनता सड़कों पर आओ। जोर से आवाज लगाओ ताकि सर्वोच्च न्यायालय के अंधे बहरे कानून और उसका पालन करवाने वाले बिके हुए या सत्ताधीशों के पाले बैठाये हुए अंकल जजों को सुनाई पड़ जाए। ईवीएम हटाओ देश बचाओ वरना सब भिखारी बन 1रु. किलो के गेहूं और 2रु. किलो के चावल की लाइन में लग गुलामी की तरह जीवन जीने में लग जाओ।

चीन ने सैन्य रसद समर्थन के लिए बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, म्यांमार पर विचार : पेंटागन रिपोर्ट

भारत की सीमा सात देशों के साथ लगती है- उत्तर-पश्चिम में अफगानिस्तान और पाकिस्तान, उत्तर में चीन, भूटान और नेपाल, सुदूर पूर्व में म्यांमार और पूर्व में बांग्लादेश। श्रीलंका (दक्षिण-पूर्व से) और मालदीव (दक्षिण-पश्चिम से) जल सीमाओं वाले दो देश हैं।

भारत के पड़ोसी देशों की सूची इस प्रकार है:

भारत के साथ कुल 9 देशों की सीमाएं लगती हैं। इनमें से 7 देश भारत के साथ जमीनी सीमा साझा करते हैं जबकि 2 देश समुद्री सीमा साझा करते हैं। भूमि सीमा की दृष्टि से भूटान भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश है।

पड़ोसी देश सीमावर्ती राज्य

अफ़ग़ानिस्तान

जम्मू और कश्मीर (POK भाग)

बांग्लादेश

पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और असम

भूटान

अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम और पश्चिम बंगाल

चीन

जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश

म्यांमार

अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड

नेपाल

सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड

पाकिस्तान

जम्मू और कश्मीर, पंजाब, गुजरात और राजस्थान

श्रीलंका

मन्नार की खाड़ी द्वारा भारत से अलग किया गया

मालदीव

लक्षद्वीप द्वीप के नीचे हिन्द महासागर का दक्षिण-पश्चिम भाग

भारत के पड़ोसी देश एक नजर में

1- अफगानिस्तान
सीमा की लंबाई- 106 किमी
आधिकारिक भाषाएँ - दारी, पश्तो
मुद्रा - अफगानी अफगानी

2- बांग्लादेश
सीमा रेखा - 4096.7 कि.मी
राजभाषा-बंगाली
मुद्रा - बांग्लादेशी टका

3- भूटान
सीमा रेखा - 699 किमी
राजभाषा - ज़ोंगखा
मुद्रा – नगुल्ट्रम

4- चीन
सीमा रेखा - 3488 किमी
राजभाषा - मंदारिन
मुद्रा – चीनी युआन

5- म्यांमार
सीमा रेखा - 1643 कि.मी
राजभाषा - बर्मी
मुद्रा - बर्मीज़ क्यात

6- नेपाल
सीमा रेखा - 1751 कि.मी
राजभाषा - नेपाली
मुद्रा-नेपाली रुपया

7- पाकिस्तान
सीमा रेखा - 3323 किमी
राजभाषा – उर्दू
मुद्रा – पाकिस्तानी रुपया

8- श्रीलंका
सीमा रेखा - समुद्री सीमा
राजभाषा - सिंहल, तमिल
मुद्रा – श्रीलंकाई रुपया

9- मालदीव
सीमा रेखा - समुद्री सीमा
राजभाषा - धिवेही
मुद्रा - मालदीवियन रूफ़िया

चीन और रूस के बाद भारत की दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अंतरराष्ट्रीय सीमा है, और यह दुनिया की सबसे संवेदनशील सीमा भी है जो चरम जलवायु परिस्थितियों से लेकर घुसपैठ तक भिन्न होती है। तो, यह भारत के पड़ोसी देशों की उपर्युक्त सूची थी जो कई शैक्षणिक और प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में पूछी जा सकती है।

भारत के पड़ोसी देशों की सूची - महत्वपूर्ण तथ्य

भारत और चीन के बीच प्राचीन काल से ही ऐतिहासिक संबंध रहे हैं। पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर हमारे द्विपक्षीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ। हालाँकि, 1962 में एक सीमा विवाद के परिणामस्वरूप दोनों देशों के बीच युद्ध हुआ। समय के साथ भारत और चीन के बीच रिश्ते सुधारने की कोशिशें होती रही हैं।

भारत और पाकिस्तान कभी एक एकीकृत देश का हिस्सा थे, एक साझा विरासत और संस्कृति साझा करते थे। हालाँकि, प्रमुख संघर्षों और, हाल ही में, कारगिल संघर्ष ने दोनों देशों के बीच संबंधों को तनावपूर्ण बना दिया है। फिर भी, पाकिस्तान के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।

दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (SAARC) की स्थापना आपसी सहयोग के माध्यम से क्षेत्र में शांति, स्थिरता और आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई थी। भारत ने पाकिस्तानी शासन से आजादी के संघर्ष में बांग्लादेश के लोगों का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इससे दोनों देशों के बीच मजबूत राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों का विकास और रखरखाव हुआ है।

पुलिस कमिश्नरी संगठित अपराधियों को पालने और वसूली करने के लिए

पेज 1 का शेष

भास्कर की यह दो रिपोर्ट मेरे ऊपर वर्णित सच को स्वयं सिद्ध कर रहे हैं पर प्रशासनिक अधिकारियों और मंत्रियों मुख्यमंत्री से लेकर देश के गृहमंत्री तक सबको देश पूरा अपराधियों के चुंगल में फंसा लूटने के लिये है। जनता हर कदम पर हर क्षेत्र में लुटती पिसती मरती रहे। देश की आने वाली पीढ़ी को चारों तरफ यथा आंखें खुलते ही मोबाइल में डुबो कर स्कूलों कॉलेज जाते समय नशे में, अश्लीलता, पढ़ाई के नाम ऑनलाइन पढ़ाई से अनेकों किस्म के अपराधों, उल्टी सीधी हरकतों संदेशों वीडियो से सोशल साइटों में, लेनदेन के समय मोबाइल से एटीएम पेटीएम भीम गूगल रिलायंस एयरटेल आदि से लेनदेन करने में घेरकर, चारों तरफ बिकते हुए घातक रसायनों के, शराब गांजा अफीम कोकिन हेरोइन एलसीडी आदि के नशे में डुबो हर तरह से भविष्य बर्बाद किया जाता रहे। उनकी बला से, उन्हें केवल धन चाहिए ताकि चुनावों के समय वह धन लुटा कर जालसाजी से सत्ता हथिया कर देश विदेश में मौज मस्ती कर सकें।

नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की ताजा रिपोर्ट

इंदौर की बड़ी चिंता- औसत 8% की दर से बढ़ रहे महिलाओं, बच्चों के खिलाफ अपराध

नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की ताजा रिपोर्ट ने इंदौर की चिंता बढ़ा दी है। बच्चों के साथ जुर्म में इंदौर देश में चौथे तो महिलाओं के खिलाफ अपराध में पांचवें नंबर पर आया है। हद यह है कि ये आंकड़े हर साल औसत आठ फीसदी की दर से बढ़ रहे हैं। कमिश्नरी सिस्टम लागू होने के बाद भी इसमें कोई बदलाव नहीं आया।

एक्सपर्ट का कहना है कि सुधार के लिए महिला सुरक्षा अधिकारी जैसे प्रयोग कागजी साबित हुए। अधिकारियों की नियुक्ति तो हुई, लेकिन उन्हें संसाधन नहीं दिए गए। ऐसी ही स्थिति साइबर क्राइम की है। कानून 15 साल पुराना हो चुका है, जबकि इस अवधि में अपराध के तौर-तरीकों में जमीन-आसमान का फर्क आ गया है।

भास्कर ने एक्सपर्ट्स पैनल के साथ पिछले तीन सालों के अपराधों के आंकड़ों की पड़ताल की। इंदौर में 2021 में 14 हजार 336 तो 2022 में 15 हजार 158 और 2023 में अब तक 16 हजार 490 अपराध दर्ज हुए हैं। यानी औसत एक हजार अपराध हर वर्ष बढ़ रहे हैं। महिला और बच्चों के साथ होने वाले लैंगिग अपराधों में 2021 से 2022 के बीच 11 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जबकि 2023 नवंबर तक यह दर 6 प्रतिशत के करीब है।

आदतन अपराधियों द्वारा किए जा रहे अपराधों का ग्राफ

एक साल में ही लूट के केस चार गुना बढ़ गए

अपराध	2021	2022	2023
लैंगिग व अन्य	9034	10043	10568
लूट	78	60	256
दुष्कर्म	272	323	306
नकबजनी	425	422	546
चोरी	589	597	713
डकैती	5	0	2
डकैती की साजिश	35	53	26
अपहरण	596	624	673
मारपीट	1804	2023	2670
साइबर क्राइम	406	130	171

नोट- उक्त आंकड़े एनसीआरबी (पीएचक्यू) को इंदौर पुलिस द्वारा भेजे गए हैं।

कमिश्नरी के 2 साल; दोगुना अफसर बढ़े

अपराध नहीं घटे, लूट में 230%, दुष्कर्म में 16% का इजाफा, जबकि हत्या के मामले 18% तो लैंगिक अपराधों में 19% तक बढ़े

इंदौर में पुलिस कमिश्नरी सिस्टम को दो साल पूरे हो गए हैं। 9 दिसंबर 2021 को कमिश्नरी सिस्टम लागू करने के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ था। अपराधों पर नियंत्रण के उद्देश्य से पुलिस कमिश्नरी तो लागू हो गई, अफसर भी लगभग दोगुना बढ़ गए, लेकिन अपराध पर नियंत्रण फिर भी नहीं हो सका।

दो साल में लूट के मामले 230 फीसदी तो दुष्कर्म के मामले 16 फीसदी बढ़े हैं। चोरी 38 फीसदी तो हत्या के मामलों में भी 18 फीसदी का इजाफा हुआ। लैंगिक अपराध (बच्चों के यौन शोषण से जुड़े) भी 19 फीसदी बढ़े हैं।

कमिश्नरी लागू होने के बाद 48 अफसर बढ़े, कुल 93 हुए

01 पुलिस कमिश्नर
01 ग्रामीण आईजी
03 एडिशनल कमिश्नर
08 डीसीपी
01 एसपी ग्रामीण
01 एसपी अजाक
13 एडिशनल डीसीपी,
30 एसीपी
35 टीआई

कमिश्नरी सिस्टम से पहले 45 अफसर थे

01 आईजी
01 डीआईजी
02 एसपी
06 एडिशनल एसपी
35 टीआई

कमिश्नरी से पहले सालभर में 38 हत्या, कमिश्नरी के बाद 45

अपराध	2021	2022	2023
लूट	78	60	258
चोरी	589	597	814
दुष्कर्म	272	323	316
लैंगिक अपराध	9034	10043	10772
हत्या	38	56	45

(वर्ष 2023 के आंकड़े नवंबर तक के। हत्या के आंकड़े 9 दिसंबर 2023 तक के)

इवीएम की जालसाजी से सत्ता हड़पने के दुष्परिणाम

जनता तैयार रहे महंगाई से अशिक्षा-बेरोजगारी और भुखमरी के लिए या फिर इवीएम के विरुद्ध आंदोलन शुरु करे

शिक्षा स्वास्थ्य बिजली सड़कें पेट्रोल गैस डीजल के साथ खाद्य वस्तुओं की महंगाई और दुर्लभता

भाजपा ने 3 राज्यों में इवीएम की जालसाजी से सत्ता हड़प ली है। इसके दुष्परिणाम भोगने के लिए तैयार रहना होगा क्योंकि मध्य प्रदेश में शिवराज ने जाते-जाते भी चार लाख करोड रुपए का जो कर्ज लिया है उसके ब्याज के रूप में भी लगभग 40 से 50000 करोड रुपए प्रति माह ही चुकाना पड़ेगा। स्वाभाविक है वह डकैत लुटेरे तो लूट कर चले गए। परंतु प्रदेश में जनता को उसकी कीमत महंगाई और आधारभूत आवश्यकताओं जैसे शासकीय बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेट्रोल डीजल गैस पर टैक्स बढ़ाने के साथ आप देख ही रहे हैं कि प्रदेश में परिवहन पंजीयन का केंद्र सरकार के गजट नोटिफिकेशन में दी गई दरों की अपेक्षा 10 गुना ज्यादा तक लूट हो रही है। दूसरी तरफ इन सरकारी संस्थाओं में खर्च कम करने के नाम पर भी मध्य प्रदेश में जो तांडव मचा हुआ है। लगभग 5 लाख से ज्यादा संविदा और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों, जिसमें अधिकांश शासकीय विभागों में लगे कंप्यूटर ऑपरेटरों, शिक्षा, स्वास्थ्य, वन, विद्युत मंडल की विद्युत वितरण उत्पादन पारेषण में लगे, नगर निगम पालिकाओं में लगे सफाई, कृषि, उद्यानिकी, लोक निर्माण विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय, जल संसाधन, विकास प्राधिकरणों, महिला बाल विकास कर्मियों को जो नियमितीकरण की बात करते थे उनको भी खर्च कम करने के नाम पर हटाने बेरोजगारी से भूख से करने का षड्यंत्र किया जाएगा।

दूसरी तरफ नेताओं ने जो चुनाव लड़ा है। उसका खर्चा भी भू कॉलोनी, ड्रग्स, शराब, स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन, ठेका, जुआ, सट्टा, वेश्यावृत्ति, वन कटाई, दलालों, माफियाओं जिनमें अधिकांश में भाजपा के नेता भी शामिल होने के साथ स्वयं भी ऐसे व्यापार संचालित कर मोटी कमाई करके हीन केवल पार्टी को धन देते हैं अपनी जगह बनाते हैं। चुनाव लड़ते हैं, के साथ उद्योगपतियों, व्यापारियों, कंपनियों से वसूलने का षड्यंत्र करने के लिए विभिन्न प्रकार की शासकीय नियमों कानून की परेशानियां खड़ी कर वसूली के नए रास्ते खोजे जाएंगे।

अब चुकी केंद्र और 3राज्यों में भी भाजपा की सरकारी बैठेंगे तो शासकीय संपत्तियां यथा विद्युत वितरण कंपनियां उत्पादन पारेषण में लूट के षडयंत्रों के रूप में अदानी के आयातित कोयले के नाम पर 3 से 5% तक कीमत बढ़ाने के साथ-साथ स्मार्ट मीटर लगाकर भी 10 गुना ज्यादा लूटने के षड्यंत्रों को अंजाम देने के बाद में भी भुखेरा जन पार्टी मोटे कमीशन पर इन कंपनियों को अब अपने खास मित्रों अडानी अंबानी टाटा बिरला आदि को बेंच, गिरवी या पट्टे पर 50 साल तक को देने के लिए षड्यंत्र करेगी यही हाल तीनों प्रदेशों की सड़कों के साथ राजस्थान, मध्य प्रदेश और छतीसगढ़ के बहुमूल्य खनिजों जिसमें हीरा, स्वर्ण, लिथियम से लेकर मोनोजाइट, क्रोमोजाइट,

यूरेनियम, गैस, पेट्रोल, तांबा, एल्युमिनियम, लोहा, कोयला आदि की खदानों को भी बेचे गिरवी करने और पट्टे पर देने का षड्यंत्र कर एक तरफ पूंजीपतियों मित्रों को मजबूत करेगी तो दूसरी तरफ वनवासियों, आदिवासियों किसानों की जमीनों को हड़पने के लिए कानून लगाकर मार काट मचाएगी। पूंजीपतियों के रखेलों की सरकार है उसकी निगाहें यही तक सीमित नहीं है सार्वजनिक सड़कों के साथ लाखों करोड़ की शैक्षणिक संस्थाओं के भवनों, मैदानों, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों, छात्रावासों, चिकित्सा, अभियांत्रिकीय, प्रबंधन, कृषि, उद्यानिकी, खेलकूद एवं शारीरिक प्रशिक्षण शिक्षण महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों को बेंचने, गिरवी करने पट्टे पर देने का षड्यंत्र कर आम गरीब आदमी को शिक्षा को पूंजीपति और दलालों के हाथ में सौंप कर महंगा करने से एक तरफ वंचित कर देगी तो दूसरी तरफ दुर्लभ बनाकर जो सक्षम है उनका भरपूर लुटवाती रहेगी।

इसी तरह का सारा प्रयोग लूट और डकैती सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों विश्वविद्यालयों से लेकर जिला अस्पतालों से गांव में निर्मित किए या स्थापित प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों का भी कर जनता को हाथ हर तरह लुटवाने के साथ धनाभाव में मृत्यु के लिए खुला छोड़ जनसंख्या कम करने का षड्यंत्र करेगी जैसा कि उसने कोरोना काल में किया था।

इवीएम से चुनाव करवाने और 20 साल से सत्ता में भाजपा की जमे रहने के दुष्परिणामों में सरकारी कर्मचारी, अधिकारियों, संविदा दैनिक वेतन भोगियों, शिक्षा कर्मियों, ठेका कर्मियों, को जोड़ो परिणाम मध्य प्रदेश में झेलना पड़ रहे हैं वही जो परिणाम अब राजस्थान और छतीसगढ़ में भी सभी सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों को झेलने पड़ेंगे, जिसमें अधिकारियों को जैसे मध्य प्रदेश में पिछले 20 साल से भर्तीयां न करने के साथ पदोन्नतियों

पुलिस कमिश्नरी संगठित अपराधियों को पालने और वसूली करने के लिए

पिछले 3 साल के एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं 99% अपराध दर्ज नहीं होते, फिर भी अपराध लगातार बढ़ रहे

देश की केंद्र सरकार में आपराधिक जाहिल मोदी की सत्ता संभालने के बाद पूरे देश में चारों तरफ न केवल व्यक्तिगत वरन संगठित अपराधियों माफियाओं देसी विदेशी आपराधिक बहुराष्ट्रीय कंपनियों का हर स्तर पर हर क्षेत्र में चाहे वह नशीली वस्तुओं के व्यापार से लेकर औद्योगिक क्षेत्र, शिक्षा, धर्म, खाद्य वस्तुओं यथा नकली दूध, शक्कर, घी, तेल अनाज, दालें, औषधीयों में मिलावट, वस्त्रों में कपास के सूती के नाम पर सिंथेटिक, भू कॉलोनी, नकली शराब, मालिश व सौंदर्य वृद्धि के नाम वेश्यावृत्ति, मकान दुकान कार्यालय माफियाओं से, सोशल साइट, डेबिट क्रेडिट कार्ड, वोटर आईडी, आधार कार्ड से, मोबाइल नंबरों से, बीमा पॉलिसी से, अस्पतालों की साइटों से जानकारी व डाटा लेकर बैंक खातों में सेंध लगाना, बीमारी का घर परिवार का डाटा ले बड़ी-बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां यथा गूगल माइक्रोसॉफ्ट अमेजॉन वॉलमार्ट रिलायंस एयरटेल तक व्यक्तिगत डाटा लेकर स्वयं संगठित उपभोक्ता वस्तुओं सेवाओं में अपराध करने के साथ अपराधों को बढ़ावा देने में पीछे नहीं है।

और यही कारण था कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां माफियाओं के इशारे पर और उनसे मोटा पैसा लेकर तड़ीपार गृहमंत्री अमित शाह ने प्रदेश के इंदौर भोपाल में 2 साल पूर्व 9 दिसंबर 2021 को पुलिस कमिश्नरी प्रणाली थोपी गई। ताकि वह सारे माफ़िया फलते-फूलते और मोटा धन प्राप्त करते रहें। आम जनता पिसती लुटती रहे। यदि आम जनता शिकायत करने भी जाए तो वो ऐसे हजारों मामले न्यायालयों तक न पहुंचे। पुलिस थानों में अगर फरियादी से शिकायत रिपोर्ट लेकर जाए तो उनको डरा धमका कर अदम चेक काट कर भगा दिया जाए और बदले में ऐसे माफियाओं से मोटी वसूली की जाए क्योंकि हर थाने में सिपाहियों से लेकर सहायक, उप व निरीक्षकों, सहायक उप अधीक्षक, सहायक उप महा निरीक्षक तक सब प्रभार में मोटा प्रभार लेकर ही, महीना चुकाने के लिये बैठाये जाते हैं। स्वाभाविक है, जो धन प्रभार के रूप में चुकाया हैऔर महीना चुकाना है के लिए वसूली करना आवश्यक है।जो केवल संगठित अपराधियों को संरक्षित कर उनके व्यवसाय में सहयोग कर अपराधियों आरोपियों को संरक्षण देकर ही प्राप्त हो सकता हैतो स्वाभाविक है बदले में न केवल व्यक्तिगत वरन संगठित भू कॉलोनी शराब शबाब, नशा, चिकित्सा, जुआ सट्टा, क्रिकेट का सट्टा, आदि बाजू वसूली बाजों, परिवहन नकली मिलावटी खाद्य पदार्थों कॉल सेंटर आदि माफियाओं को पाल पोस संरक्षित कर महीना वसूलकर के अपने आकाओं को पहुंचाया जा सकता है जिसके बदले मेंआप देख रहे हैं लगातार अपराधों की वृद्धि इंदौर भोपाल में हो रही है।

(शेष पेज 7 पर)

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक- अजमेरा एस.पी. कुमार द्वारा अपनी दुनिया प्रिंटर्स, 13 प्रेस कॉम्प्लेक्स, ए.बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 299, अम्बेडकर नगर, इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित।
संपादकः अजमेरा एस.पी. कुमार, मो. 9425125569, भोपाल प्रतिनिधि- एस.के. भारद्वाज मो. 9425637958